दर्जनों बेकसूर पत्रकारों को गिरफ्तार कराने वाले अर्नब की गिरफ़्तारी पर क्यों मचा रहे हैं शोर

सैकड़ों बेकसूर कथित देशद्रोह के आरोपी जेलों में बंद, कभी भाजपाइयों ने उनके बारे में सोचा?

शिवम विज

बुधवार सुबह रिपब्लिक टीवी वाले अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी होते ही नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों, भाजपा नेताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों की तरफ से तत्काल इसकी निंदा की जाने लगी। इसकी उम्मीद भी की जानी चाहिए थी।

हालांकि, ध्रुवीकरण के इस दौर में हम उदारवादियों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे उदारवादियों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खड़े हों। फिर भी हमने तमाम उदारवादियों को अर्णब की गिरफ्तारी को भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के साथ-साथ स्पष्ट राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए इसकी निंदा करते देखा। कई उदारवादियों ने तो यहां तक कहा कि वे अर्णब की विच-हंट जर्नलिज्म से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं है।

जब राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उदारवादी पत्रकारों या कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो हमें दक्षिणपंथियों की तरफ से ऐसी उदारता देखने को नहीं मिलती। कोई नहीं कहता, 'मैं प्रशांत कनौजिया की राजनीति से असहमत हूं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।' या 'मेरी राजनीति सुधा भारद्वाज से अलग है लेकिन उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है।'

भारत के विभिन्न हिस्सों में कितने सारे लोग सिर्फ इसलिए केस झेल रहे हैं या जेल में समय बिता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए का विरोध करने की हिमाकत की थी, लेकिन हमें ऐसा कोई दक्षिणपंथी नजर नहीं आया जिसने इसे आजादी पर हमला बताते हुए इसकी निंदा की या सिर्फ राजनीतिक मतभिन्नता करार दिया।

अन्वय नाइक के लिए न्याय?

कश्मीर में एक अखबार का कार्यालय बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रेस की आजादी का उल्लंघन केवल तभी हुआ जब अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया।अजब बात है जब कोई सबूत नहीं था तब अर्णब गोस्वामी की अगुआई में तमाम टीवी चैनलों ने सुशांत सिंह को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और यहां तक की हत्या के आरोप में भी संदेह के आधार पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर अभियान चला रखा था।

सुशांत सिंह राजपूत ने अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था जबकि अन्वय नाइक ने ऐसा किया था. अन्वय नाइक ने अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी और दो अन्य लोगों पर बकाया भुगतान न किए जाने को अपनी जान देने की वजह बताया था। उनका परिवार उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है। अगर राजपूत की तरफ से सुसाइड नोट न छोड़ने के बाद भी Justice For SSR सही था, तो JusticeForAnvayNaik क्यों नहीं?

कृपया ध्यान दें कि गोस्वामी को सोनिया गांधी या आदित्य ठाकरे के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है।उन्हें पालघर में साधुओं की हत्या की घटना पर अपने चैनल पर की गई टिप्पणियों के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया गया जिसे उन्होंने बेवजह सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की थी। उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं के खिलाफ 'दुष्प्रचार अभियान' के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। यदि उन्हें इनमें से किसी के लिए गिरफ्तार किया गया होता तो आप इसे बोलने की आजादी पर हमला कह सकते थे। लेकिन उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जब वाम-उदारवादियों को राजनीतिक कैदियों के रूप में जेल में डाला जाता है तो दक्षिणपंथी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। फिर अर्णब गोस्वामी के मामले में 'अपना काम' करना कानून पर क्यों नहीं छोड़ देते?

वैसे अर्णब की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारण से हुई है, कृपया यह भी ध्यान दें कि 2018 में जब आत्महत्या की यह घटना हुई तब वहां भाजपा की सरकार थी और मुंबई पुलिस ने उस समय मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया था। यदि आत्महत्या के मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी आज राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो सकती है तो 2018 में समान आरोपों पर उन्हें छोड़ दिए जाने को राजनीतिक संरक्षण कहा जा सकता है।

दूसरे शब्दों में कहें तो अर्णब गोस्वामी को जैसे को तैसा वाला जवाब मिल रहा है। भारत अब आधिकारिक रूप से राजनीतिक विचारधाराओं के दोनों पक्षों की तरफ से कानूनी उत्पीड़न और राजनीति प्रेरित मामलों पर उतर आया है। यह भयावह है, लेकिन पहले आग किसने लगाई?

स्वतंत्रता, दूसरे शब्दों में

मोदी सरकार के कितने मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश में बच्चों के सरकारी स्कूलों में फर्श पर झाड़ू लगाने संबंधी रिपोर्ट दिखाने वाले पत्रकारों की गिरफ्तार की आलोचना की? योगी आदित्यनाथ के यूपी में जब सरकारी स्कूल में मिडडे मील के लिए रोटी और नमक परोसे जाने का खुलासा करने पर एक पत्रकार के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया तब कहां पर थे हमारे दक्षिणपंथी और प्रेस की आजादी के लिए उनकी चिंता? भाजपा को आपातकाल की याद उस समय क्यों नहीं आई जब भाजपा शासित यूपी में एक पत्रकार को भूमि विवाद पर रिपोर्टिंग के लिए मार डाला गया?

स्मृति ईरानी कहती हैं कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी 'फासीवाद' है, लेकिन हमने उनकी तरफ से तब कुछ भी नहीं सुना जब तमिलनाडु में एक पत्रकार को कोविड-19 की कवरेज के कारण गिरफ्तार किया गया। कोविड लॉकडाउन के दौरान कश्मीर में पत्रकारों को जब पुलिस ने हिरासत में लिया और कथित तौर पर उन्हें पीटा तब प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रकाश जावड़ेकर की चिंता कहां थी? गुजरात में जब एक पत्रकार को केवल इसलिए गिरफ्तारी और देशद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने राज्य में मुख्यमंत्री बदले की संभावना पर एक स्टोरी की थी तब कितने लोगों ने व्यापक स्तर पर निंदा की थी?

मोदी सरकार कोर्ट में तर्क दे रही है कि पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह के आरोप नहीं हटाए जाने चाहिए। उनका अपराध? क्या किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया? क्या किसी सुसाइड नोट में उन्हें दोषी ठहराया गया? नहीं। केवल मोदी सरकार की आलोचना करना.

यह समझ से परे है कि अर्णब गोस्वामी क्यों त्रिपुरा के एक पत्रकार पाराशर बिस्वास की तुलना में अधिक स्वतंत्रता के हकदार हैं, जिन्हें कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर मीडिया को मुख्यमंत्री बिप्लब देब की धमकी की आलोचना के बाद पीटा गया था।

सिद्धांतों की बात

उदारवादियों की तरफ से अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा किए जाने की बात तो समझ में आती है क्योंकि वे लगातार राजनीतिक प्रतिशोध, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले और प्रेस की स्वतंत्रता के हनन के रूप में कानूनी कार्रवाई की निंदा करते रहे हैं।

उदारवादियों ने उन पत्रकारों के पक्ष में आवाज उठाई जो हाल में हाथरस गैंगरेप और हत्या की घटना को कवर करने की कोशिश के तौर पर अपना काम कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उस समय कौन चुप था या उनकी गिरफ्तारी को सही ठहरा रहा था? ये वही लोग थे जो फर्जी आरोपों के आधार पर रिया चक्रवर्ती को 'घेरने' में अर्णब गोस्वामी को चैंपियन बना रहे थे।

जब दक्षिणपंथी अर्णब गोस्वामी की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये उनका पाखंड है क्योंकि उनके लिए बोलने की आजादी व्यक्ति के राजनीतिक रुख पर निर्भर है।हालांकि, उदारवादी अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालने का विरोध करते हैं।

यदि दक्षिणपंथी इस सिद्धांत से सहमत हो पाएं और राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए बिना राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करना शुरू करें तो हम स्वतंत्र, बेहतर, पवित्र देश बन सकेंगे।

गौरतलब : एक तरफ भाजपा की गोद में बैठा अर्नब, दूसरी तरफ संघर्षरत मजदूर मोर्चा का मामला

आत्महत्या करने वाले द्वारा नामजद दोषी ठहराये जाने वाले अर्नब गोस्वामी की जायज गिरफ़्तारी पर तमाम भाजपा नेताओं को इमरजेंसी की याद आ गयी। इस गिरफ्तारी को प्रेस की आज़ादी पर हमला बताने वाले तमाम भाजपाई नेताओं को केवल अपने पालतू अर्नब में ही लोकतंत्र का चौथा खंबा नज़र आता है।

14 अगस्त 2019 को एनआईटी फ़रीदाबाद के डीसीपी विक्रम कपूर ने गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। उनके सुसाइड नोट में मज़दूर मोर्चा सम्पादक सतीश कुमार का नाम तक न होने के बावजूद तत्कालीन सीपी संजय कुमार ने एफ़आईआर में उनका नाम घुसेड़ कर उन्हें गिरफ़्तार करने के लिये अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। उसने यह कार्यवाही 'मोर्चा' द्वारा उसके भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित करने का बदला लेने के लिये की थी। करीब तीन सप्ताह पागल कुत्ते की तरह घूमती पुलिस से बचते बचाते संपादक सतीश ने हाई कोर्ट से राहत पाई। इसके बाद पुलिस तफतीश में शामिल होने पर पुलिस को भी उनके विरुद्ध कुछ नहीं मिला था।

यहां सवाल यह पैदा होता है कि सतीश का 'मज़दूर मोर्चा' क्या लोकतंत्र का चौथा खंबा नहीं था जो उस वक्त सारे भाजपाई नेता व मीडिया वाले मुंह में दही जमाये बैठे थे? उस वक्त उन्हें मीडिया एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई?

करनाल का मोर्चा

अग्रवाल समाज को भी मिले सरकारी नौकरियों में हिस्सा: बजरंग

करनाल(म.मो) अग्रोहा धाम अग्रोहा विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने अग्रोहा धाम के प्रदेश महासचिव रमेश जिंदल व अन्य प्रतिनिधियों को महाराजा अग्रसेन का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम की तरफ से जरूरतमंद अग्रवाल युवक-युवतियों की शादी कराने, महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित लघु फ़िल्म बनाने, पहली मिलनी महाराजा अग्रसेन के नाम पर निकालने, देश के हर राज्य में जनता की सेवा के लिए करोड़ों रुपये की लागत से अयोध्या के साथ-साथ अग्रोहा धाम के भवन बनाने, शादी में कार्ड की जगह निमंत्रण वाट्सऐप के माध्यम से देने आदि बातों को गंभीरता से लागू करना चाहिए।

करनाल में सफाई न होने पर लगी फटकार

करनाल (जेके शर्मा)= स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साफ-सफाई के अभाव में यहां कई खामियां नजर आई। उन्होंने सम्बधित अधिकारी को फटकार भी लगाई। निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेन्द्र चोपड़ा को साफ-सफाई रखने के आदेश दिए।

इस मौके पर शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था दुरस्त न होने के कारण जिला कार्यक्रम अधिकारी राजबाला को कहा कि स्वच्छता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्राथमिकता का विषय है। इसमें कतई लापरवाही न बरतें। उन्होंने कार्यालय में पेड़ों की छटाई के लिए एक्स.ई.एन होर्टिकल्चर नरेश त्यागी को भी निर्देश दिए और कहा कि सूखे पेड़ों व गिरे हुए पेड़ों को तुरन्त उठवाएं तथा जो सूखे पेड़ है उन्हें कटवाया जाए।

5 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन

करनाल (जेके शर्मा) हरियाणा टूरिज्म संघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों को लेकर विरोध मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सुरेश पाल, रामकुमार व गुलाब सिंह ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार विभाग को बेचने की नीयत से निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। आज तक सातवें वेतन का 65 प्रतिशत एरियर भी नहीं मिला। पिछले पांच महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही है, जिससे तमाम कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है।

इस अवसर पर मदन लाल, कर्मवीर, ओमप्रकाश, सत्यपाल, बलवान, रामकुमार, गुलाब सिंह व सुरेश पाल मौजूद रहे।

राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रदर्शन

करनाल (ममो) केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया।

कर्मचारी फव्वारा पार्क में जिला प्रधान मलकीत सिंह की अध्यक्षता में जुटे। मुख्य सचिव हरियाणा के नाम 26 नवंबर की हड़ताल करने का नोटिस दिया गया।

कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान मलकीत सिंह, जिला सह सचिव सुशील गुर्जर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शारदा व जिला आडिटर अनिल सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी को अवसर में बदलकर जनता के खून पसीने से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि भारत कोल,भारत पैट्रोलियम, भारतीय रेल, भारतीय दूरसंचार, एयर इंडिया व अन्य नवरत्न जो जनता की सुविधा के लिए खड़े किए गए थे वह पूंजीपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके राज की कठपुतली बनाया जा रहा है। कर्मचारियों पर एकतरफा अनेक आर्थिक कटौतियां करके आर्थिक हमले किए जा रहे हैं। इसी प्रकार श्रम कानूनों को समाप्त किया जा रहा है,काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जा रहे हैं।

हरियाणा के संदर्भ में 1983 पीटीआई समेत हजारों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है और अब उन्हें समायोजित करने के नाम पर भद्दा मजाक किया गया है।

इस अवसर पर जिला उपप्रधान जगमाल, विजय शर्मा, नरेश, कर्मवीर, अंकित राणा, सुरेश, भाग सिंह, सेवा राम, वाईपी यादव, बलराज, संदीप बलड़ी अजीत, सुरेंद्र शर्मा, जयपाल, कुलदीप, शिव कुमार व बुद्ध राम ने विचार रखें।